The issue of appointing an Executive Director on a permanent basis is linked with the implementation of this recommendation.

**Test for recruitment in CPWD**

3754. SHRI THANGABAALU: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether a test (Theory on 21st, 22nd and 23rd January, 1985) and Practical on (15th, 16th, 18th, 28th 29th May and 3rd June, 1985) was held in Delhi zone for promotion from the post of Mistry/Operator/Fitter to the post of Sr. Mechanic/Air conditioning and Refrigeration, Division 1, C.P.W.D., New Delhi;

(b) whether all the persons who qualified have been absorbed; if not the reasons therefor;

(c) whether any new test is proposed to be held for recruitment to the post of Senior Mechanic; if so, the reasons therefor; and

(d) the steps taken to absorb persons who qualified in 1985?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes.

**(b) to (d) Till now, only those** who qualified in the trade test held in the earlier years, and who happen **to be senior in the panel, could be absorbed.** As per rules/orders, trade test is to be held every year in respect of all those who are eligible and such test cannot be deferred till they become due for promotion. This is in order that those who do not pass the trade test in the first attemp be **enabled to make special effort to pass the** same well before they become due for consideration for promotion. Those who have qualified in the trade test held in the year 1985, will be absorbed in their turn, as and when vacancies occur.

**मत्स्य पालन के लिए धनराशि का आवंटन**

3755. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में मत्स्य पालन परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और क्या इसका मूल्यांकन किया जाएगा कि इस क्षेत्र के कार्य में वास्तव में कोई विस्तार हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि गंगा और अन्य नदियों में पुराने तरीकों से मछवाही का जा रही है और इन नदियों के लिए न तो अभी तक कोई मछली विकास योजना आरम्भ की गई है और न ही मछवाहों को मछली पकड़ने के आधुनिक साधन उपलब्ध करवाए गए है ; और

(ग) क्या कारण है कि देश के भीतरी जलाशयों में मछली विकास की कोई बड़ी परियोजना नहीं है जबकि समुद्री मछवाही परियोजना पर 80 प्रतिशत धनराशि व्यय की जा रही है ?

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा)** (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मत्स्य पालन विकास के लिए 566.63 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :--

(करोड रुपए)

| | |
|---|---|
| केन्द्रीय सरकार | 217.35 |
| राज्य सरकारें | 329.19 |
| भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (भा कृ अ प०) | 18.75 |
| राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (रा स०वि०नि०) | 1.34 |
| | 566.63 |

योजना आयोग ने अब तक प्राप्त की गई प्रगति का मूल्यांकन करने और इस क्षेत्र में विस्तार की सीमा जानने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंजूर की गई मत्स्य पालन विकास संबंधी योजनाओं का मध्यावधि मूल्यांकन शुरू किया है।

(ख) जी, नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने अपने केन्द्रीय अन्तर्देशीय ग्रहण मत्स्य पालन संस्थान के माध्यम से मछली की संख्या, संरक्षण का प्रबोधन करने और मात्स्य की सम्पदा का विवेकपूर्ण उपयोग करने की पद्धतियों का विकास करने की दृष्टि से 3 मुख्य नदी प्रणालियों अर्थात गंगा, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा के ग्रहण मत्स्य संसाधनों का अन्वेषण कर रहा है। प्रत्येक 5 हैक्टेयर के आकार के 4 मलजल पोषण मछली फार्मों को स्थापित करने की परिकल्पना में जलकृषि के लिए जैव अवशिष्ट (मलजल) का उपयोग करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयन के लिए 128 लाख रुपए की कुल लागत पर मंजूर की गई है। वह परियोजना गंगा नदी में प्रदूषण को रोकने में सहायक होंगी।

(ग) जलाशयों में मछली पालन विकास की परियोजनाएं शुरू करने की मुख्य अड़चने पर्याप्त मात्रा में डिम्भोत्पन्न का न मिलना, जलाशय के मात्स्य की के बेहतर प्रबंध तथा उपयोग के लिए अवस्थापन त्मक सुविधाओं का न मिलना विवेकपूर्ण भंडारण, प्रबंध, संचयन तथा संचयन के बाद की प्रक्रियाओं के अभाव है। तथापि, सी० आई० सी० एफ० आर० आई० के सरोवरी मात्स्यकी प्रभाग ने देश में जलाशय मत्स्यकी तथा विकास संबंधी समस्याओं पर कार्य करना शुरु किया है। भारत सरकार के पास सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 13 करोड़ रुपए की कुल लागत पर गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के राज्यों में जलाशय मात्स्यकी विकास परियोजना शुरू करने का एक प्रस्ताव भी है।

3756.[Transferred to the 9th December, 1987].

**Setting up of sugar factories in Karnataka**

3757. SHRI VEERSHETTY MOGLAPPA KUSHNOOR: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) what is the target fixed in the Seventh Five Year Plan period for sugar production in the country, how many licences have been issued for expansion and seting up of new industries in the country upto the end of October, 1987 and to what capacity; and

(b) how many applications have been received from Karnataka for expansion and setting up of new sugar industries how many of them are pending for issue of licences till the end of October, 1987?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI H K L. BHAGAT): (a) In the Seventh Plan document a production target of 102 lakh tonnes of sugar for 1989-90 is envisaged. After the announcement of new guidelines for licensing in the Sugar Industry during the Seventh Five Year Plan, 11 Letters of Intent for establishment of new 2500 TCD sugar plants and 39 for substantial expansion in the expasion and settig up of new sugar production capacity of 9.81 lakh tonnes have been issued upto 31st October, 1987.

(b) (i) Applications received for setting up of new sugar units—Nil.

(ii) Applications received and approved for expansion in the existing units—3.

(iii) Applications pending—Nil.

**National Fertilizer unit at Vijaypur in Madhya Pradesh**

3758. SHRI AJIT P. K. JOGI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the National Fertilizers Limited unit at Vijaypur in Madhya Pradesh